

अमरनाथ यात्रा 2026

सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम

ड्रोन, डॉग स्क्वॉड और 670 CAPF कंपनियां रहेंगी तैनात



जम्मू-कश्मीर में होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तैयार किया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने यात्रा की सुरक्षा के लिए 670 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दी है। यह अमरनाथ यात्रा के इतिहास में सबसे बड़ा सुरक्षा प्रबंध माना जा रहा है। यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से मोर्चा संभालेंगी।

सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा मार्ग, लंगर स्थलों और ठहराव केंद्रों पर ड्रोन सर्विलांस बढ़ाया जाए तथा डॉग स्क्वॉड के माध्यम से लगातार जांच की जाए।

पूरे मार्ग पर रहेगा सुरक्षा घेरा

सुरक्षा बलों की तैनाती लक्ष्मणपुर (लखनपुर) से लेकर पवित्र गुफा तक की जाएगी। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों, बेस कैंपों, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, यात्री निवासों और ट्रांजिट कैंपों को विशेष सुरक्षा कवच में रखा जाएगा। हाल के वर्षों में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए इस बार तकनीक आधारित निगरानी को प्राथमिकता दी गई है। ड्रोन, CCTV नेटवर्क, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक इकाइयों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, श्रद्धालुओं को सुरक्षित

- » सुरक्षा व्यवस्था की प्रमुख बातें
- » 670 CAPF कंपनियों की तैनाती
- » संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से 24 घंटे निगरानी
- » डॉग स्क्वॉड द्वारा एंटी-सबोटाज जांच
- » बम निरोधक दस्तों की विशेष तैनाती
- » स्नाइपर टीमों और विक्क रिएक्शन टीमों की मौजूदगी
- » हाईवे और यात्रा मार्गों पर रोड ओपनिंग पार्टियां (ROP)
- » हाई-रिजॉल्यूशन CCTV कैमरों से निगरानी
- » प्रमुख कैंपों और लंगरों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था

और निर्बाध यात्रा अनुभव प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया है।

तेलंगाना के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई, लोगों की तारीफ में कही ये बातें



तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी समेत देश के तमाम नेताओं ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने बधाई देते हुए कहा कि यह राज्य अपनी गौरवशाली संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है।

उन्होंने राज्य की जनता के अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कहा 'तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर तेलंगाना की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं. तेलंगाना के लोग अपनी नवाचार और उद्यमिता और दृढ़ संकल्पके लिए जाने जाते हैं. यह राज्य अपनी गौरवशाली संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है.साहस और दृढ़ संकल्प की कहानी।

विकास के लिए समर्थन का भरोसा

पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में तेलंगाना की महत्वपूर्ण भूमिका है और केंद्र सरकार इस दिशा में राज्य को हर संभव सहयोग प्रदान करती रहेगी. उन्होंने कहा 'केंद्र सरकार विकसित भारत के हमारे सपने को साकार करने में तेलंगाना के विकास पथ को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है'. उन्होंने कहा कि तेलंगाना अपनी गौरवशाली संस्कृति, समृद्ध इतिहास और साहसिक परंपराओं के लिए पूरे देश में पहचान रखता है. उन्होंने राज्यवासियों के उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि की कामना भी की।

राष्ट्रपति मुर्मू ने की सराहना

इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी तेलंगाना की जनता को राज्य की स्थापना के अवसर पर बधाई दी. उन्होंने तेलंगाना संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत और मेहनती लोगों की सराहना की. मुर्मू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा राज्य ने पिछले कुछ सालों में नवाचार और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

लोकतंत्र में संवाद की जगह नहीं ले सकती सतही नारेबाजी

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति विचारों का संघर्ष और संवाद की संस्कृति होती है। सत्ता और विपक्ष के बीच मतभेद स्वाभाविक हैं, बल्कि यही लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवंत बनाए रखते हैं। लेकिन जब राजनीतिक विमर्श तथ्यों और तर्कों की बजाय आरोपों, कटु भाषा और नारेबाजी पर आधारित होने लगे, तब यह लोकतंत्र की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर की गई टिप्पणी ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया। 'देशद्रोह' जैसा आरोप भारतीय राजनीति में साधारण शब्द नहीं माना जाता। यह ऐसा गंभीर आरोप है जिसके समर्थन



में ठोस तथ्य और प्रमाण अपेक्षित होते हैं। लोकतंत्र में असहमति और आलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन आलोचना तब अधिक प्रभावी होती है जब वह तथ्यों और तर्कों पर आधारित हो। अन्यथा वह केवल राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाती है।

भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में अपने अंतिम संबोधन के दौरान चेतावनी दी थी कि लोकतंत्र में जब संवैधानिक और शांतिपूर्ण रास्ते उपलब्ध हों, तब असंवैधानिक तरीकों और अमर्यादित भाषा का प्रयोग अंततः अराजकता को जन्म देता है। आज के राजनीतिक माहौल में यह चेतावनी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक दिखाई देती है।

40-50 गांवों की सेहत भगवान भरोसे

बामौरकलां PHC में डॉक्टर नहीं, सिर्फ दो कर्मचारियों के सहारे चल रही स्वास्थ्य व्यवस्था

अतुल जैन

30 साल पुराने स्वास्थ्य केंद्र में अधिकांश पद रिक्त, ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से लगाई गुहार

बामौरकलां। शिवपुरी जिले के अंतिम छोर पर स्थित बामौरकलां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर वर्षों से चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी से जूझ रहा है। हालत यह है कि लगभग 40 से 50 गांवों की आबादी को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-346 (भिंड-भोपाल मार्ग) पर स्थित होने के बावजूद क्षेत्र के लोगों को मामूली उपचार के लिए भी दूर-दराज के अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार तथा क्षेत्र में भाजपा विधायक होने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। चिकित्सकों और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।

1996 में हुआ था स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ

बामौरकलां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ 28 अक्टूबर 1996 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री प्रेम नारायण ठाकुर ने तत्कालीन विधायक के.पी. सिंह की अध्यक्षता में किया था। स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, एएनएम, कंपाउंडर, नेत्र सहायक, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एवं वार्ड बॉय सहित कुल 10 पद स्वीकृत हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। यहां केवल एक एएनएम और एक फार्मासिस्ट ही कार्यरत हैं, जबकि शेष सभी पद वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र का संचालन नाममात्र के संसाधनों से किया जा रहा है।



झोलाछाप डॉक्टरों का बढ़ रहा नेटवर्क

चिकित्सकों की कमी का फायदा झोलाछाप डॉक्टर उठा रहे हैं। मजबूरी में ग्रामीण इन्हीं के पास उपचार कराने पहुंचते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो किसी भी समय गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

आठ उप स्वास्थ्य केंद्र भी स्टाफ संकट से प्रभावित

खनियांधाना ब्लॉक बामौरकलां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आठ उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। इनमें से कई केंद्रों पर भी पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन कार्यक्रम और अन्य स्वास्थ्य योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

पूरे खनियांधाना ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाएं संकट में

खंड चिकित्सा अधिकारी ने स्वीकार किया है कि केवल बामौरकलां ही नहीं बल्कि पूरे खनियांधाना विकासखंड में स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी बनी हुई है। अधिकारियों के अनुसार विकासखंड के 41 सब-सेंटर्स में से 23 सब-सेंटर्स ऐसे हैं जहां सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) नहीं

हैं। 19 सब-सेंटर्स में एएनएम के पद रिक्त हैं, जबकि 6 सब-सेंटर्स ऐसे हैं जहां एएनएम और CHO दोनों ही उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा 16 सब-सेंटर्स में आशा सुपरवाइजर के पद भी खाली पड़े हैं।

विकासखंड के तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

बामौरकलां, मुहारीकलां और अछरौनी-वर्तमान में चिकित्सक विहीन हैं। इसके अलावा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के अधिकांश पद भी रिक्त हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे गए प्रस्ताव

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को पत्राचार किया जा रहा है। विभाग द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि शासन स्तर पर जल्द ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

जनता की मांग-तत्काल ही नियुक्तियां

क्षेत्रीय जनता ने केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी तथा जिला कलेक्टर से मांग की है कि वर्षों से रिक्त पड़े चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के पदों को तत्काल भरा जाए, ताकि ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

इनका कहना है

हमारे पूरे खनियांधाना ब्लॉक में बहुत सारे पद रिक्त हैं, जिसके संबंध में हम समय-समय पर स्टाफ मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार कर रहे हैं और प्रयास किए जा रहे हैं कि रिक्त स्थानों पर मानव संसाधन उपलब्ध हो सकें। हमारे पूरे विकासखंड में 41 सब-सेंटर्स हैं, जिनमें से 23 सब-सेंटर्स में CHO नहीं है हमारे पास, एवं 19 सब-सेंटर्स में हमारे पास ANM भी नहीं हैं, एवं 6 सब-सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें ANM एवं CHO दोनों ही पदस्थ नहीं हैं। एवं हमारे पास 16 सब-सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें आशा सुपरवाइजर के पद रिक्त हैं। इसी प्रकार हमारे तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बामौरकलां, मुहारीकलां एवं अछरौनी, तीनों ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक विहीन संस्थाएं हैं। इसी प्रकार हमारे विकासखंड में भी कुछ चिकित्सक और अन्य पैरामेडिकल के पद हैं, उनमें से अधिकांश पद रिक्त हैं, जिससे हमारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और इसके संबंध में हमने वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार किया है और प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन पदों पर हमें मानव संसाधन उपलब्ध हो सकें। जो अभी हमारी चर्चा हुई है और जो हमने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में पूरा परिपत्र लाया है तो हमें यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उन पदों पर मानव संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएंगे, एवं इस दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं।

**अरुण झाव्या
बीएमओ खनियांधाना**



सांसद लालवानी ने देखा कचरा प्रबंधन मॉडल, परिषद ने रखी जेसीबी की मांग

दरबार सिंह ठाकुर

देपालपुर। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने सोमवार को देपालपुर प्रवास के दौरान नगर परिषद क्षेत्र में संचालित स्वच्छता एवं विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड क्रमांक-4 स्थित ट्रेडिंग ग्राउंड पहुंचकर नगर से एकत्रित होने वाले गीले एवं सूखे कचरे के प्रसंस्करण एवं पृथक्करण के लिए स्थापित मशीनों का अवलोकन किया तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। सांसद ने ट्रेडिंग ग्राउंड परिसर में कचरा प्रबंधन व्यवस्था का जायजा लेते हुए परिषद अधिकारियों से संचालन एवं रखरखाव संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्वच्छता कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। इसके बाद

सांसद लालवानी ने वार्ड क्रमांक-5 स्थित सूरजकुंड का निरीक्षण किया तथा श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर दर्शन-पूजन किया। इस दौरान क्षेत्र की विकास संभावनाओं और नागरिक सुविधाओं को लेकर भी चर्चा हुई। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद प्रतिनिधियों ने परिषद की वित्तीय चुनौतियों से सांसद को अवगत कराया। परिषद के पास आवश्यक संसाधनों की कमी का उल्लेख करते हुए सफाई एवं अन्य कार्यों के सुचारु संचालन के लिए जेसीबी मशीन उपलब्ध कराने की मांग रखी गई। सांसद ने मांग पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नगर परिषद उपाध्यक्ष गोपाल

कटेशरिया, वरिष्ठ पार्षद विमल यादव, सांसद प्रतिनिधि अजय आहूजा, पार्षद रवि चौरसिया, मोहरसिंह नागर, सोमिल माली, सतीश मारू, बबलू पहलवान, शिवम सोनी, विकास पांचाल, मुख्य



नगर पालिका अधिकारी बहादुरसिंह रघुवंशी, स्वच्छता उपनिरीक्षक शैलेश कुराडिया, उपयंत्री नीरज गुप्ता, उमेश सोलंकी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

मथुरा में 'IIT बाबा' गिरफ्तार: प्रवचन की आड़ में युवतियों को फंसाने और ब्लैकमेलिंग का आरोप

उत्तर प्रदेश के मथुरा में खुद को "IIT पास बाबा" बताने वाले एक कथित धर्मगुरु को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रवचनों के जरिए युवकों और युवतियों, विशेषकर संपन्न परिवारों की लड़कियों को अपने प्रभाव में लेता था और फिर उनका आर्थिक तथा मानसिक शोषण करता था। पुलिस जांच के अनुसार आरोपी धार्मिक प्रवचन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के नाम पर लोगों से संपर्क बढ़ाता था। इसके बाद वह उन्हें अपने आश्रम या निजी ठिकानों पर बुलाकर कथित तौर पर अनुचित गतिविधियों में शामिल करता था। आरोप यह भी है कि वह कुछ मामलों में तथाकथित "गंधर्व विवाह" कराकर युवतियों को अपने जाल में फंसाता था।

ब्लैकमेलिंग और वसूली के आरोप-जांच एजेंसियों के मुताबिक

आरोपी पर युवतियों की निजी जानकारी और तस्वीरों का दुरुपयोग कर ब्लैकमेल करने तथा उनसे बड़ी रकम वसूलने के आरोप भी लगे हैं। पुलिस को कई डिजिटल साक्ष्य और शिकायतें मिली हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच की जा रही है।

सोशल मीडिया से बनाया नेटवर्क-पुलिस का कहना है कि आरोपी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अपना बड़ा अनुयायी वर्ग तैयार किया था। प्रवचन, धार्मिक वीडियो और आध्यात्मिक संदेशों के माध्यम से वह लोगों का विश्वास जीतता था और फिर उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता था। कई और खुलासों की संभावना-पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों को आशंका

श्री वासुदेव चन्द्रवंशी यादव समाज और श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा 6 जून को प्रतिभाओं और मातृशक्तियों का होगा 'नागरिक अभिनंदन'

पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल होंगे मुख्य अतिथि

इंदौर। श्री वासुदेव चन्द्रवंशी यादव समाज संघ के तत्वावधान में आगामी 6 जून को सुबह 10 बजे से रीगल चौराहा स्थित 'इंडियन कॉफी हाउस' में एक भव्य सम्मान समारोह और नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्री वासुदेव चन्द्रवंशी यादव समाज संघ के अध्यक्ष मदन परमालिया ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह भव्य आयोजन गीता रामेश्वरम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न होगा। इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक कर्दम करेंगे।

वंचित वर्ग की सेवा और सामूहिक विवाह की पहल को सम्मान



ज्योति यादव मोहिनी यादव शशि यादव कमलेश यादव अनुपम यादव रश्मि सिंह

इस वर्ष समाजसेवा के क्षेत्र में विशिष्ट और अतुलनीय योगदान देने वाली मातृशक्तियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा है। "अमृतम सेवा संस्थान" के माध्यम से समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्ग के जीवन में 'अमृत' घोलने तथा समाज के सहयोग से कन्याओं का निःशुल्क सामूहिक विवाह संपन्न कराने जैसी सराहनीय पहल के लिए संस्थान की संचालिका को "चंद्रवंशी यादव महिला गौरव सम्मान" (समाज गौरव अवार्ड) से अलंकृत किया जाएगा। समाज के कल्याण और उत्थान के लिए किए जा रहे उनके इस 'टीम वर्क' की सराहना करते हुए समाज संघ खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

कोटा से आए जोड़ों के सामूहिक विवाह पर मातृशक्तियों का बहुमान...

इस अवसर पर उन मातृशक्तियों का भी विशेष रूप से नागरिक अभिनंदन किया जाएगा, जिन्होंने कोटा से विशेष रूप से पथारे जोड़ों का संपूर्ण रूप से 'निःशुल्क सामूहिक विवाह' संपन्न करवाकर समाज का नाम पूरे देश में रोशन किया है। इस पुनीत कार्य में गीता रामेश्वरम ट्रस्ट की भूमिका भी बेहद सराहनीय रही है। इसी क्रम में, समाज हित और सेवा कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली क्षेत्र की प्रतिष्ठित मातृशक्तियों को भी इस भव्य मंच से विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसमें ज्योति यादव, मोहिनी यादव, शशि यादव,

कमलेश यादव, अनुपम यादव और रश्मि सिंह को उनकी उल्लेखनीय सहभागिता और समाज सेवा के लिए नागरिक अभिनंदन कर सम्मानित किया जाएगा।

75% से अधिक अंक लाने वाले

प्रतिभावान छात्र-छात्राएं होंगे पुरस्कृत

मातृशक्तियों के साथ-साथ यह कार्यक्रम समाज की युवा पीढ़ी और भविष्य को भी समर्पित रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज के ऐसे होनहार लड़के-लड़कियों को भी मंच से सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने परीक्षाओं में 75% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं। समाज संघ का मानना है कि इन बच्चों को प्रोत्साहित करने से समाज में शिक्षा का स्तर और मजबूत होगा। मदन परमालिया ने बताया कि सभी पदाधिकारियों ने समाज के प्रबुद्ध जनों से मंगलवार को आयोजित बैठक में इस समारोह में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराने की अपील की है, ताकि सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं और मातृशक्तियों का उत्साहवर्धन किया जा सके।

अन्नामलाई ने BJP से दिया इस्तीफा, तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा भूचाल

चेन्नई। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष K. Annamalai ने पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष Nitin Nabin से मुलाकात कर औपचारिक रूप से इस्तीफा दिया। इस घटनाक्रम ने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है और उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, अन्नामलाई ने इस्तीफा देने से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की। लंबे समय से उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच तमिलनाडु में गठबंधन रणनीति, विशेषकर AIADMK के साथ संबंधों को लेकर मतभेदों की चर्चा चल रही थी।

नई पार्टी बनाने की चर्चा

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अन्नामलाई आने वाले महीनों में एक नई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार उनकी प्रस्तावित पार्टी "द्रविड़ियन 2.0" जैसी अवधारणा पर आधारित हो सकती है, जो तमिल पहचान और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगी।

भाजपा के लिए बड़ा झटका

पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई को दक्षिण भारत में भाजपा का उभरता चेहरा माना जाता था। उनके नेतृत्व में भाजपा ने तमिलनाडु में संगठन विस्तार की कोशिश की थी। ऐसे में उनका इस्तीफा राज्य में भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।

दो दिन में हो सकता है बड़ा ऐलान

अन्नामलाई ने हाल ही में अपने भविष्य को लेकर पूछे गए सवालों पर संकेत दिया था कि वह जल्द ही अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। अब उनके इस्तीफे के बाद तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना बढ़ गई है।



राजनीतिक संदेश

अन्नामलाई का यह कदम केवल एक इस्तीफा नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या वह नई पार्टी बनाते हैं, किसी अन्य राजनीतिक मोर्चे का हिस्सा बनते हैं या फिर राज्य की राजनीति में कोई नया प्रयोग करते हैं।

ट्रेडिंग से KYC तक... एक दिन में 8 शिकार और 20 लाख की लूट

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में साइबर ठगों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे, KYC अपडेट, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने, कार्ड बंद होने और पेंशन कार्ड अपडेट जैसे झांसे देकर साइबर अपराधी लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। हालात ये हैं कि सिर्फ एक दिन में साइबर ठगी के रिकॉर्ड 8 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें लोगों से करीब 20 लाख 54 हजार रुपये की ठगी की गई है। पुलिस लोगों से सतर्क रहने और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने की अपील कर रही है। ग्वालियर में साइबर अपराधियों के नए-नए हथकंडे सामने आ रहे हैं। कहीं फेसबुक पर दोस्ती कर कारोबारी को ट्रेडिंग के नाम पर 8 लाख 20 हजार रुपये का चूना लगाया गया, तो कहीं KYC अपडेट के नाम पर बैंक खातों से रकम उड़ा ली गई। सिर्फ एक दिन में दर्ज 8 मामलों ने पुलिस और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है।



निष्काम कर्म ही है आध्यात्मिक उन्नति का सच्चा मार्ग

मानव जीवन कर्म आधारित है। कर्म के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए सफल और सार्थक जीवन के लिए कर्म आवश्यक है। किंतु कर्म तभी श्रेष्ठ बनता है जब उसमें



स्वीकार होता है जो पूर्णतः निष्काम भाव से किया गया हो। सहज योग में इस अवस्था को प्राप्त करने का एक अत्यंत सरल और प्रभावी मार्ग है। ध्यान के माध्यम से इड़ा (बाई) और पिंगला (दाहिनी)

नाड़ियों का संतुलन स्थापित होता है, जिससे अहंकार और प्रति-अहंकार की प्रवृत्तियाँ धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं। तब साधक के भीतर यह ज्ञान स्थापित होता है कि कार्य करने की शुद्ध प्रेरणा भी ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त होती है और उसे पूर्ण करने की शक्ति भी ईश्वर ही प्रदान करता है। इस सत्य का अनुभव होने पर व्यक्ति समझता है कि वास्तविक कर्ता और करवाने वाला ईश्वर है, जबकि हम केवल उसके माध्यम हैं। ईश्वर का माध्यम बनने की यह अनुभूति गहन शांति, संतोष और आनंद प्रदान करती है। आइए, हम सभी सहज योग से जुड़कर ध्यान की इस सरल एवं प्रभावशाली विधि को सीखें तथा अपने जीवन को अधिक शांत, संतुलित और आनंदमय बनाएं। सहज योग ध्यान केंद्र सभी नए साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। सहज योग के बारे में अधिक जानकारी हेतु टोल-फ्री नंबर 1800-270-0800 पर या वेबसाइट www.sahajayoga.org.in पर संपर्क कर सकते हैं। सहज योग पूर्णतः निःशुल्क है।

सहज योग में साधकों को निष्काम भाव से कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जब किसी साधक में कर्ता भाव उत्पन्न होने लगता है, तो वह उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन जाता है। सहज योग में अनेक सेवाएँ और कार्य होते हैं, किंतु यदि कोई साधक उन कार्यों के माध्यम से प्रसिद्धि या प्रशंसा प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वह निष्काम सेवा के मूल उद्देश्य से दूर हो जाता है। ईश्वर को वही कर्म

नहिं

अल नीनो की आहट से बारिश पर मंडराया संकट!

प्रशांत महासागर की गहराइयों से उठ रही एक अदृश्य चुनौती अब पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज बदलने और भारत पर कहर बरपाने को तैयार खड़ी है। दरअसल यह कोई साधारण मौसमी बदलाव नहीं, बल्कि 'अल नीनो' नामक वह प्राकृतिक घटना है, जिसकी आहट मात्र से ही बाढ़, सूखे और भयंकर लू का तांडव मचने की आशंका गहरा जाती है। क्या होता है अल नीनो? दरअसल मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का समय-समय पर गर्म होना ही अल नीनो कहलाता है। यह गर्माहट इतनी प्रचंड होती है कि रेन सिस्टम में होने वाला मामूली सा डिस्टर्बेंस भी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेता है। अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मौसम विशेषज्ञों ने इस बार अटलांटिक तूफान को सामान्य से शांत रहने का अनुमान लगाया है, जिसके पीछे अल नीनो का ही हाथ बताया जा रहा है। विशेषज्ञों की मानें तो सामान्य से कम तूफानी गतिविधि की 55 प्रतिशत संभावना है, जबकि सामान्य से अधिक गतिविधि की संभावना महज 10 प्रतिशत ही है।

क्या इस बार अल नीनो का असर दिखाई देगा?

वहीं अटलांटिक तूफान का मौसम



जून की शुरुआत से 30 नवंबर तक चलता है, जिसमें तूफानी गतिविधियाँ सितंबर के मध्य में अपनी चरम पर होती हैं। लेकिन अल नीनो के चलते इस बार अटलांटिक में तूफानों का जोर कुछ कम रह सकता है। हालांकि, प्रशांत महासागर में पैदा होने वाली यह मौसमी घटना दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़, सूखे और लू की तीव्रता को बढ़ाने का काम करती है। अपने सक्रिय चरण के दौरान यह वैश्विक औसत तापमान को भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ा देती है, जिससे हर तरफ हाहाकार मचने का खतरा रहता है।

'ला नीना' क्या है?

दरअसल अल नीनो की घटनाएं आमतौर पर हर 2 से 7 साल में एक

बार दस्तक देती हैं और इनका प्रभाव 9 से 12 महीने तक कायम रहता है। इसके विपरीत 'ला नीना' है, जिसका अर्थ प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से ठंडा होना है। अल नीनो के दौरान हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या अपनी दिशा बदल लेती हैं, जिससे प्रशांत महासागर का गर्म पानी वापस पूर्व की ओर अमेरिका के तटों की ओर बहने लगता है। यह अटलांटिक तूफानों की गतिविधियों को कम करता है, जबकि प्रशांत महासागर में तूफानों की गतिविधियों को बढ़ा देता है। एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ आफत का यह खेल प्रकृति का ही अजब करिश्मा है। भले ही अल नीनो की शुरुआत प्रशांत महासागर में होती हो, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया में किसी भूचाल से कम नहीं होता।

बामौरकलां में विवाहिता की मौत का खुलासा, पति और ससुर पहुंचे सलाखों के पीछे

अतुल जैन

पुलिस जांच में प्रताड़ना के आरोप पाए गए सही, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला दर्ज

बामौरकलां। शिवपुरी जिले के बामौरकलां थाना क्षेत्र के ग्राम सेकरा में एक महिला की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका को लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमती यांगचेन डोलकर भुटिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं अनुविभागीय

अधिकारी पुलिस पिछोर प्रशांत शर्मा के निर्देशन में गंभीर अपराधों में आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।

खेत पर बनी टपरिया में फंदे पर लटका मिला था शव

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 मई 2026 को ग्राम सेकरा निवासी दीक्षा यादव (31) पत्नी कृष्णपाल यादव ने खेत पर बनी टपरिया में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मार्ग क्रमांक 09/2026 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की थी। घटना के बाद पुलिस ने मृतका के परिजनों, ग्रामीणों तथा अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान सामने आया कि विवाह के बाद से ही मृतका को उसके पति एवं ससुर द्वारा घरेलू कामकाज और अन्य बातों को लेकर लगातार परेशान और प्रताड़ित किया जाता था।



जांच में प्रताड़ना के आरोप पाए गए सही

मार्ग जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने पाया कि मृतका दीक्षा यादव अपने पति कृष्णपाल यादव और ससुर रामसहाय यादव की प्रताड़ना से मानसिक रूप से परेशान थी। लगातार मिल रही प्रताड़ना से तंग आकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए जाने पर थाना बामौरकलां में अपराध

क्रमांक 70/2026 के तहत धारा 108 एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

एक जून को हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने मामले में आरोपी कृष्णपाल यादव (33 वर्ष) पुत्र रामसहाय यादव एवं रामसहाय यादव (66 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय मेहरवान सिंह यादव, दोनों निवासी ग्राम सेकरा थाना बामौरकलां को 1 जून 2026 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ की गई तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूर्ण की गई। मंगलवार 2 जून को दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय खनियाधाना में पेश किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश जारी किए।

आरोपियों का रहा है आपराधिक इतिहास

पुलिस अभिलेखों के अनुसार आरोपी रामसहाय यादव के विरुद्ध पूर्व में हत्या, बलवा, मारपीट एवं धमकी जैसे गंभीर अपराधों सहित सात आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं आरोपी कृष्णपाल यादव के विरुद्ध भी मारपीट, धमकी, आर्म्स एक्ट सहित पांच मामले दर्ज पाए गए हैं।

पुलिस का कहना है कि आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है तथा मामले की विवेचना जारी है।

इन पुलिसकर्मियों की रही सराहनीय भूमिका

पूरे मामले की जांच एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बामौरकलां संजय लोधी, उपनिरीक्षक दिनेश पाण्डेय, प्रधान आरक्षक दिनेश प्रताप सिंह, आरक्षक राहुल लोधी, आरक्षक सुनील कुमार योगी एवं चालक आरक्षक सत्यवीर गुर्जर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर 4 से 9 जून तक NOTAM जारी

भुवनेश्वर। भारत ने ओडिशा तट स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से एक महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 4 जून से 9 जून तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर विशेष NOTAM (Notice to Air Missions) जारी किया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि

यह किसी अत्याधुनिक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल या उन्नत सामरिक प्रणाली के परीक्षण से जुड़ा हो सकता है। जारी NOTAM के तहत बंगाल की खाड़ी के एक बड़े हिस्से को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है, ताकि परीक्षण के दौरान नागरिक विमानों और समुद्री

यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस तरह के बड़े प्रतिबंधित क्षेत्र आमतौर पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक या रणनीतिक मिसाइलों के परीक्षण से पहले बनाए जाते हैं।

अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, भारत के प्रमुख मिसाइल

परीक्षण केंद्रों में से एक है। यहां से अग्नि, ब्रह्मोस, आकाश, अस्त्र और अन्य कई सामरिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया जा चुका है। हाल के महीनों में इसी क्षेत्र से लंबी दूरी की मिसाइलों और MIRV क्षमता से लैस उन्नत अग्नि मिसाइलों के परीक्षण भी हुए हैं।

तिरुपति में आस्था का नया रिकॉर्ड, एक माह में 12.4 लाख श्रद्धालुओं ने चढ़ाए बाल

तिरुपति (आंध्र प्रदेश)। विश्व प्रसिद्ध तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में श्रद्धा का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के अनुसार मई 2026 में 27 दिनों के भीतर 12.43 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने सिर मुंडवाकर अपने

हजार से अधिक श्रद्धालु केशदान करते रहे, जिससे सभी पुराने रिकॉर्ड पीछे छूट गए।

1152 नाई दे रहे हैं सेवा

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए TTD ने विशेष व्यवस्था की है। तिरुमाला में विभिन्न केंद्रों पर 1,152 नाई, जिनमें 269 महिला नाई भी शामिल हैं, 24 घंटे सेवा दे रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार न करना पड़े।

बालों से होती है करोड़ों की आय

तिरुपति में चढ़ाए गए बाल केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि मंदिर की आय का भी बड़ा स्रोत हैं। इन बालों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीलामी होती है और उनसे विंग, कॉस्मेटिक तथा अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। बालों की बिक्री से मंदिर को हर वर्ष करोड़ों रुपये की आय होती है।

आस्था का अनूठा प्रतीक

हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर के प्रति समर्पण और मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु अपने बाल अर्पित करते हैं। यही कारण है कि तिरुपति में केशदान की परंपरा सदियों से चली आ रही है और हर वर्ष लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं। तिरुपति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आस्था के आगे दुनिया के सारे रिकॉर्ड छोटे पड़ जाते हैं।



बाल भगवान वेंकटेश्वर को अर्पित किए, जो अब तक का एक नया कीर्तिमान माना जा रहा है।

गर्मी की छुट्टियों और भीड़ ने बनाया रिकॉर्ड

TTD के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष गर्मी की छुट्टियों और लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या के कारण केशदान करने वालों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई। 27 मई तक 12,43,063 श्रद्धालु बाल अर्पित कर चुके थे, जबकि पिछले वर्षों में यह संख्या काफी कम थी।

एक दिन में 57 हजार से ज्यादा लोगों ने कराया मुंडन

मंदिर प्रशासन के अनुसार 23 मई को अकेले 57,580 श्रद्धालुओं ने मुंडन कराकर बाल अर्पित किए। कई दिनों तक प्रतिदिन 50

मई माह में इंदौर मंडी की आय में सुधार, 13 माह बाद दर्ज हुई वृद्धि

खुशबू श्रीवास्तव

इंदौर। कृषि उपज मंडी समिति इंदौर की मई 2026 की आय के आंकड़ों में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। मंडी समिति द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 13 महीनों के बाद मंडी की वास्तविक मासिक आय में वृद्धि दर्ज की गई है। मई 2025 में जहां वास्तविक मंडी शुल्क प्राप्ति 4 करोड़ 28 लाख 28 हजार 966 रुपये थी, वहीं मई 2026 में यह बढ़कर 4 करोड़ 31 लाख 44 हजार 367 रुपये हो गई। इससे मंडी की आय में सकारात्मक वृद्धि का संकेत मिला है।

हालांकि अप्रैल-मई 2026 की संचयी अवधि में मंडी शुल्क प्राप्ति 8 करोड़ 93 लाख 64 हजार 871 रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में यह आंकड़ा 10 करोड़ 26 लाख 95 हजार 630 रुपये था। मंडी समिति का कहना है कि आयातित तुअर (दलहन) पर दी गई छूट और गेहूं उपार्जन से प्राप्त होने वाले मंडी शुल्क के कारण वास्तविक आय प्रभावित दिखाई दे रही है।

समिति के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में आयातित तुअर पर 1 करोड़ 56 लाख 86 हजार 902 रुपये की छूट दी गई है। वहीं गेहूं उपार्जन से मंडी समिति को 1 करोड़ 61 लाख 3 हजार 9 रुपये मंडी शुल्क प्राप्त होना है। यदि शासन के नियमानुसार उपार्जन का मंडी शुल्क प्राप्त हो जाता है तथा दलहन पर दी गई छूट को भी आय में शामिल किया जाए, तो मंडी समिति की कुल संभावित आय 12 करोड़ 11 लाख 54 हजार 782 रुपये तक पहुंच सकती है। इस स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17.97 प्रतिशत की वृद्धि



दर्ज होगी। वहीं केवल मई माह के आंकड़ों में यह संभावित वृद्धि 48.93 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। मंडी समिति के सचिव ने बताया कि वित्तीय प्रबंधन और व्यापारिक गतिविधियों में सुधार के चलते आय में सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। शासन स्तर से प्राप्य राशि प्राप्त होने पर मंडी की वित्तीय स्थिति और अधिक मजबूत होगी।



आयुक्त सह प्रबन्ध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल

छापा पड़ा, माल उड़ा, मालिक गायब... अब रिपोर्ट किसे पकड़ाएगी प्रशासन?

करैरा/शिवपुरी

हेमंत भार्गव

करैरा अनुविभाग अंतर्गत नया अमोला और टीला गांव में संचालित कथित अवैध पान मसाला एवं तंबाकू फैक्ट्री पर करीब 15 दिन पहले प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा था। उस समय जिला खाद्य विभाग की टीम ने मौके से पान मसाला और तंबाकू के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे तथा पंचनामा बनाकर रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया था। लेकिन अब 15 दिन बाद जब हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया तो दृश्य कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। जहां कभी फैक्ट्री संचालित होने की बात कही जा रही थी, वहां अब न माल दिखाई

दे रहा है और न ही मालिक का कोई अता-पता। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो फैक्ट्री नहीं, कोई जादुई तंबू था जो प्रशासनिक कार्रवाई के बाद हवा में उड़ गया।

जनता पूछ रही है-रिपोर्ट आएगी तो जाएगी किसके नाम?

स्थानीय लोगों की जुबान पर इन दिनों एक ही सवाल है कि जिन दो स्थानों से नमूने लिए गए थे, उनकी जांच रिपोर्ट आखिर कब आएगी? और यदि रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई किस पर होगी?

क्योंकि मौके पर न माल मौजूद है, न मशीनें और न ही संचालक। ऐसे में ग्रामीण तंज कसते हुए पूछ रहे हैं कि क्या जांच रिपोर्ट सीधे खाली मैदान को थमाई जाएगी या फिर गायब मालिक को खोजने

के लिए नई जांच समिति गठित होगी?

छापा था या सिर्फ फोटो सेशन?

ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि प्रशासन ने जिस जोर-शोर से कार्रवाई की थी, उससे लगा था कि बड़ा खुलासा होने वाला है। लेकिन 15 दिन बाद स्थिति यह है कि पूरा मामला “जांच जारी है” की फाइलों में घूम रहा है, जबकि माल और मालिक दोनों मैदान छोड़ चुके हैं।

लोगों का कहना है कि यदि जांच रिपोर्ट आने तक पूरा सामान और संबंधित लोग ही गायब हो जाएं तो फिर छापा का उद्देश्य क्या रह जाता है? क्या कार्रवाई सिर्फ पंचनामा तैयार करने तक सीमित थी या फिर किसी को समय देकर सुरक्षित निकास का रास्ता उपलब्ध कराया गया?

मैदान साफ, सवाल बरकरार

नया अमोला और टीला में आज स्थिति यह है कि जहां कभी पान मसाला और तंबाकू निर्माण की चर्चाएं थीं, वहां अब केवल खाली स्थान दिखाई देता है। लेकिन आम जनता के मन में सवाल का धुआं अभी भी उठ रहा है—

क्या जांच वास्तव में चल रही है?

क्या रिपोर्ट आने के बाद कोई ठोस कार्रवाई होगी?

या फिर यह मामला भी “रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई होगी” के सरकारी गलियारों में ही घूमता रहेगा? फिलहाल सच इतना ही है कि छापा के 15 दिन बाद माल भी नहीं है, मालिक भी नहीं है, लेकिन जांच अभी भी जारी बताई जा रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन की रिपोर्ट पहले आती है या फिर जनता के सवालों का सब खत्म होता है।

कल्याणी में गंदगी, जलभराव और अनियमितताओं से घिरा अंबेडकर भवन

ग्रामीणों ने प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई

दिव्यानंद अर्गल

ग्वालियर । जनपद पंचायत डबरा की ग्राम पंचायत कल्याणी में विकास कार्यों और पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। गांव का अंबेडकर भवन लंबे समय से बदहाली का शिकार बना हुआ है। भवन परिसर में चारों ओर गंदगी फैली हुई है, जबकि पास से गुजरने वाले नाले का गंदा और बदबूदार पानी लगातार परिसर में भर रहा है। इससे भवन की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर बना यह भवन गांव की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है, लेकिन पंचायत की अनदेखी के कारण इसकी हालत जर्जर हो गई है। परिसर में जलभराव और गंदगी के चलते लोगों को यहां आने-जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कई बार शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई गांव के कुबेर सिंह, रणवीर, संतोष, भारत, छोटू और पवन सहित अन्य ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत और सरपंच से अंबेडकर भवन की मरम्मत, साफ-सफाई और नाले की समस्या के समाधान की मांग की, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है।

नाला निर्माण में अनियमितताओं के आरोप

ग्रामीणों ने पंचायत द्वारा कराए गए नाला निर्माण कार्य पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। इसके कारण नाला कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। नतीजा यह है कि गंदा पानी सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में फैल रहा है तथा अंबेडकर भवन परिसर भी इसकी चपेट में आ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप किया गया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती। उन्होंने नाला निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।



पंचायत संचालन को लेकर भी उठे सवाल

मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पंचायत संचालन को लेकर लगाए जा रहे आरोप हैं। ग्रामीणों का दावा है कि पंचायत की निर्वाचित सरपंच गुड़ी



आदिवासी हैं, लेकिन पंचायत के अधिकांश निर्णय गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा लिए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वही व्यक्ति अधिकारियों से संपर्क कर पंचायत के कार्यों का संचालन कर रहा है। ग्रामीणों ने इसे "ठेके पर

सरपंची" बताते हुए कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि की भूमिका सीमित होकर रह गई है, जबकि पंचायत की वास्तविक कमान किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में है। उनका कहना है कि यदि आरोप सही हैं तो यह पंचायत राज व्यवस्था की मूल भावना के विपरीत है।

स्वच्छता व्यवस्था पर भी सवाल

ग्रामीणों के अनुसार गांव में स्वच्छता व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। कई स्थानों पर गंदगी फैली हुई है और नालियों का पानी सार्वजनिक स्थलों तक पहुंच रहा है। इससे मच्छरों और संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वच्छता को लेकर पंचायत के दावे केवल कागजों तक सीमित नजर आते हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनकी मांग है कि अंबेडकर भवन की तत्काल मरम्मत कराई जाए, परिसर की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए, नाले की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए तथा कथित भ्रष्टाचार और पंचायत संचालन से जुड़े आरोपों की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

इन्होंने क्या कहा

अंबेडकर भवन को हटाकर नया निर्माण कराने के लिए मैं पिछले तीन साल से सरपंच से चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक यह कार्य नहीं हो पाया है। यह बात सही है कि कुछ दबंग लोग सरपंच को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं स्वयं सरपंच से पुनः चर्चा करूंगा और शासकीय प्रक्रिया के तहत इस भवन का पुनर्निर्माण कराया जाएगा।

- सुरेश राजे, विधायक, डबरा

आपके द्वारा यह मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है, मैं अंबेडकर भवन की स्थिति और नाले की भी जांच करवाऊंगा। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमित या लापरवाही पाई जाती है तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

- उषा पी. शर्मा, जनपद सीईओ, डबरा

वेदांता समूह को बड़ा झटका: जाम्बिया में 60 दिन के लिए बंद हुआ कॉपर स्मेल्टर

वैश्विक सप्लाई और कीमतों पर पड़ सकता है असर

ई दिल्ली। वैश्विक कॉपर उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांता समूह की जाम्बिया स्थित कंपनी कोंकोला कॉपर माइंस (KCM) ने अपने प्रमुख नचांगा कॉपर स्मेल्टर को 60 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया है। कंपनी ने यह कदम प्लांट में व्यापक मरम्मत, रखरखाव और तकनीकी उन्नयन कार्यों को पूरा करने के लिए उठाया है। इस फैसले का असर न केवल जाम्बिया के खनन क्षेत्र पर बल्कि वैश्विक कॉपर बाजार और संबंधित उद्योगों पर भी पड़ सकता है। कंपनी के अनुसार यह शटडाउन उसकी दीर्घकालिक विकास रणनीति का हिस्सा है। KCM आने वाले वर्षों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है और उसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक वार्षिक कॉपर



उत्पादन को बढ़ाकर तीन लाख टन तक पहुंचाना है। जाम्बिया के खान मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने वर्ष 2025 के दौरान 80,215 मीट्रिक टन कॉपर का उत्पादन किया था। ऐसे में उत्पादन बढ़ाने की दिशा में यह रखरखाव कार्य बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि बाजार की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि यह शटडाउन ऐसे समय पर हो रहा है जब जाम्बिया के अन्य बड़े कॉपर प्रोसेसिंग प्लांट भी रखरखाव कार्यों के कारण अस्थायी रूप से बंद होने जा रहे हैं। मोपानी और चांबिशी जैसे प्रमुख कॉपर संयंत्रों में भी जून से सितंबर के बीच लंबे समय तक संचालन प्रभावित रहेगा। इससे जाम्बिया में कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के उत्पादन पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर और कोबाल्ट उत्पादन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर इसकी उपलब्धता पहले से ही चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में सल्फ्यूरिक एसिड

की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे माहौल में जाम्बिया के प्रमुख स्मेल्टरों के बंद होने से बाजार में आपूर्ति और सीमित हो सकती है।

हालांकि KCM ने स्पष्ट किया है कि वह अपने नचांगा टेलिंग्स लीच प्लांट को सल्फ्यूरिक एसिड की आपूर्ति जारी रखेगा। इसके लिए कंपनी बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से खरीद के साथ-साथ अपनी 500 टन प्रतिदिन क्षमता वाली एसिड उत्पादन इकाई का उपयोग करेगी। इसके बावजूद बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पादन और सप्लाई में संभावित कमी का असर वैश्विक कीमतों पर दिखाई दे सकता है। कॉपर को इलेक्ट्रिक वाहनों, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, पावर ट्रांसमिशन और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण धातु माना जाता है।

रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी का बड़ा खुलासा “ATM से निकाल लिया जाता है आधा वेतन”

विशेष रिपोर्ट

देश की जीवनरेखा मानी जाने वाली भारतीय रेलवे में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने ठेकेदारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

कई कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें कागजों में पूरा वेतन दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविकता में ठेकेदार विभिन्न तरीकों से उनकी मजदूरी का बड़ा हिस्सा वापस ले लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर दावा किया कि वेतन खाते में आने के बाद ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि कर्मचारियों से एटीएम कार्ड और पिन की जानकारी मांगते हैं। आरोप है कि खाते में जमा राशि में से आधा या बड़ा हिस्सा निकाल लिया जाता है, जबकि रिकॉर्ड में पूरा भुगतान दर्शाया जाता है।

कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी जाने के डर से अधिकांश लोग शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ठेका प्रणाली में काम करने वाले सफाईकर्मी, ट्रेक मेंटेनेंस स्टाफ, लोडिंग-अनलोडिंग कर्मचारी और अन्य श्रमिक आर्थिक शोषण का सामना कर रहे हैं।

श्रम कानूनों के अनुसार किसी कर्मचारी के वेतन से अवैध कटौती करना दंडनीय अपराध है। यदि ऐसे आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल श्रम कानूनों का उल्लंघन नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और मजदूरों के अधिकारों के हनन का गंभीर मामला भी है।

विशेषज्ञों का मानना है

» » रेलवे प्रशासन, श्रम विभाग और संबंधित जांच एजेंसियों को इस मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। वेतन भुगतान की डिजिटल निगरानी, कर्मचारियों की गोपनीय शिकायत व्यवस्था और ठेकेदारों के ऑडिट से ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कर्मचारियों के आरोप सही हैं, तो वर्षों से यह खेल किसकी निगरानी में चलता रहा? क्या जिम्मेदार अधिकारी इससे अनजान थे, या फिर व्यवस्था की खामियों का लाभ उठाकर मजदूरों के हक पर डाका डाला जाता रहा? मजदूरों की मेहनत पर चलने वाली व्यवस्था में यदि मजदूर ही अपने हक के वेतन से वंचित रह जाएं, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय पर भी एक गंभीर प्रश्नचिह्न है।



परीक्षा प्रणाली पर बढ़ता संकट

देश की परीक्षा व्यवस्था आज एक गंभीर विश्वास संकट से गुजर रही है। प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं अब अपवाद नहीं रह गई हैं, बल्कि वे एक ऐसी समस्या का रूप ले चुकी हैं, जिसने विद्यार्थियों, अभिभावकों और समाज के बीच परीक्षाओं की निष्पक्षता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। बोर्ड परीक्षाओं से लेकर नीट, जेईई और सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं तक, लगभग हर स्तर पर पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे लाखों मेहनती विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होता है और उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। सरकारें हर बार जांच, नई सुरक्षा व्यवस्था और कड़े कानूनों की बात करती हैं। परीक्षा संचालन की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के प्रयास भी किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं। इससे स्पष्ट है कि समस्या केवल तकनीकी सुरक्षा की नहीं, बल्कि व्यवस्था के भीतर मौजूद उन कमजोरियों की भी है, जो ऐसे अपराधों को जन्म देती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोह आखिर इतने वर्षों से सक्रिय कैसे हैं और उन्हें संरक्षण कहां से मिलता है?

इस समस्या का दूसरा और अधिक गंभीर पक्ष समाज के भीतर मौजूद मानसिकता से जुड़ा है। प्रश्नपत्र तभी बिकते हैं जब उन्हें खरीदने वाले मौजूद हों। कोई भी पेपर लीक तभी सफल होता है जब कुछ अभिभावक और विद्यार्थी अनुचित लाभ पाने के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार साल्वर गैंग तभी सक्रिय होते हैं जब शिक्षित और योग्य लोग नैतिकता से समझौता कर आर्थिक लाभ के लिए अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए यह समस्या केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक संकट भी है।

कुछ वर्ष पहले बिहार बोर्ड परीक्षा के दौरान एक छात्रा का यह बयान कि “मैं तो सेकेंड डिवीजन से पास होना चाहती थी, लेकिन चाचा

ने टॉपर बना दिया” पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। यह घटना केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं, बल्कि उस सामाजिक सोच को भी उजागर करती है जिसमें सफलता के लिए ईमानदार प्रयास से अधिक महत्व शॉर्टकट और प्रभाव को दिया जाने लगा है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि केवल बाहरी अपराधी ही नहीं, बल्कि व्यवस्था के भीतर मौजूद कुछ जिम्मेदार लोग भी ऐसे अपराधों में शामिल हो सकते हैं। जिन लोगों पर प्रश्नपत्र तैयार करने और उसकी गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, यदि वही नैतिकता से समझौता कर लें तो किसी भी सुरक्षा व्यवस्था का प्रभाव सीमित हो जाता है। यही कारण है कि केवल कानूनों को कठोर बना देना पर्याप्त समाधान नहीं हो सकता। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक ऐसी घटनाएं अपेक्षाकृत कम क्यों थीं? उस दौर में समाज में त्याग, ईमानदारी, सार्वजनिक जीवन की शुचिता और राष्ट्रहित की भावना अधिक मजबूत थी। आज आर्थिक सफलता और व्यक्तिगत लाभ की दौड़ ने कई बार सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है। महात्मा गांधी का यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि प्रकृति सभी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को नहीं। पेपर लीक जैसे अपराधों की जड़ में भी अक्सर यही लालच दिखाई देता है।

वास्तविक चिंता इस बात की है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ज्ञान और कौशल तो प्रदान कर रही है, लेकिन चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों के विकास में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। यदि शिक्षा केवल अंकों, डिग्रियों और नौकरी तक सीमित रह जाएगी, तो समाज में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मूल्य कमजोर पड़ते जाएंगे। शिक्षा का उद्देश्य केवल सफल पेशेवर तैयार करना नहीं।

त्यंग्य: सूट बूट वाला तिलचट्टा

हमारी डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है कि अब इसमें छिपकलियां और कॉकरोच तक इंस्टेंट लेने लगे हैं। यह हमारी डेमोक्रेसी के समावेशी (इन्क्लूसिव) होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। अमेरिका जब से ईरान सहित अन्य देशों के साथ युद्ध में अपने मुंह की खाने लगा है तब से मेड इन यूएस तिलचट्टा (कॉकरोच) वहां से निकल निकल कर देश की सियासत में शामिल होने के लिए हमारे यहां पहुंचने लगे हैं। दोस्तों सन् 2026 में भारत में व्हाया अमेरिका कॉकरोच जनता पार्टी (डिजिटल) लांच हुई है। मजेदार बात यह है कि इस लांचिंग का देश के विपक्ष ने खुली बाहों से ऐसे स्वागत किया है मानो कोई बेटा दुनिया ओलंपिक जीत कर स्वदेश वापस आ रहा हो। भला इतने सौहार्द की पॉलिटिक्स दुनिया के किसी और देश में कहीं देखी गई है क्या? नहीं ना। तभी तो यूं ही नहीं हमारे देश को अजूबों का देश कहा जाता है। सुटेड- बूटेड तिलचट्टे को देख कर फक्र होता है कि यहां के तिलचट्टे का वहां किस तरह मेक ओवर हो गया है। वह सुटेड बूटेड हो गया है। एक हमारे यहां के काकरोच हैं साले रसोई घरों में नंगे पुंगे घूमते रहते हैं। वे इतने शर्मदार हैं कि जैसे ही कोई महिला या पुरुष किचन में प्रवेश करता है वह शरमा कर दौड़ लगा कर छुप जाते हैं। एक

यह अमेरिका रिटर्न कॉकरोच है जो कोट पेंट और टाई से सजा धजा है। यह वैसा ही है जैसे यहां का हरीलाल फॉरेन जा कर कैसे हैरी बन जाता है। रामसिंह विदेश में जा कर रेम्सन बन जाता है।

एक वह जमाना था जब आजादी की लड़ाई के समय और उसके बाद देश की सियासत में नेताओं द्वारा टोपियां पहनी जाती थीं। बाद में यह टोपी जनता को पहनाई जाने लगी। उन टोपियों के रंग भले ही अलग अलग हों, पर उन सब की नियत और लक्ष्य एक ही होता है, जन सेवा के नाम पर अपने कुटुंब की सेवा। उनमें देश भक्ति लुप्त होती है। देश भक्ति का जिम्मा खाकी यूनिफॉर्म के पास है। देश भक्ति और जन सेवा का काम उन्हीं के जिम्मे है। जरूरी नहीं है कि नेता में देश भक्ति हो। पहले टोपी, नेता की पहचान हुआ करती थी। पर जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र जवान होता गया, नेताओं की नीयत और जमाना बदला और नेताओं ने जनता को ही टोपी पहनाना शुरू कर दिया। तब से सोसाइटी में टोपी की इज्जत घटती चली गई और उसके साथ नेताओं के सिर से टोपियां भी गायब होती चली गईं। अब उन्हीं के सिर पर टोपियां शोभायमान हैं जिन के मस्तक से केश नदारद हो गए हैं। वैसे भी मस्तक की शोभा केशों से ही होती है। लेकिन आज के जमाने

में आदमी की इज्जत केश से नहीं केश से होती है। जितना केश उतना ऐश। नेताओं ने इस मर्म को भली भांति समझा है। पहले चंदा विनम्रता और अनुरोध पूर्वक मांगा जाता था। अब अल्टीमेटम होता है।

हमारे नेताओं और लोकतंत्र के साथ अब हमारा समाज और जमाना भी मॉर्डन हो गया है। अब वो जमाना गुजर गया जब राजनैतिक दलों के चुनाव निशान समाज से जुड़े होते थे। बैलजोड़ी, गाय- बछड़ा, दीपक, शेर, हाथी हंसिया और धान की बाल या हंसिया और हथौड़ा, वट वृक्ष या झोपड़ी हुआ करता था। निर्वाचन आयोग ने अब पशु संरक्षण के नाम पर जानवरों के चुनाव निशान देना बंद कर दिया और झोपड़ी की जगह अब मल्टियां तन गई हैं। पेड़ (वट) विकास की भेंट चढ़ गए हैं। ग्रीनरी अब गमलों और बोतलों में सिमट कर पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे रही है। लोग अब वृक्षों को देखने जंगल नहीं जाते। अब वे बोन्साई प्लांट देखने एक्जीविशन में जाते हैं। यही कारण है कि आदमी की सोच और दृष्टि भी बोन्साई की तरह निरंतर लघु होती जा रही है। बोन्साई की तरह। इसी कड़ी में अब अमेरिका से फॉरेन रिटर्न चुनाव चिन्ह, सॉरी इलेक्शन सिंबल तिलचट्टा (कॉकरोच) आया है।

पश्चिम बंगाल में 'महाराष्ट्र मॉडल'

क्या फूट की ओर बढ़ रही ममता बनर्जी की TMC?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से ही वहां की सियासी फिजा लगातार बदलती जा रही है। साथ ही ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) को इस्तीफे के जरिए लगातार झटके भी लग रहे हैं।

अब वहां के सियासी गलियारे में यह चर्चा भी जोर पकड़ती जा रही है कि एक ऐसी नई तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई जाए जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी न हों। यह मामला तब सामने आया जब टीएमसी के 2 विधायकों (ऋतब्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा) को हस्ताक्षर विवाद को लेकर पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने (विसलव्दोअर बनने) के कारण पार्टी से निकाल दिया गया पार्टी की ओर से 2 विधायकों को पार्टी से निकाले जाने के बाद कई लोग अब यह सवाल भी पूछने लगे हैं कि क्या अब बंगाल में भी 'महाराष्ट्र मॉडल' दोहराए जाने की तैयारी चल रही है? क्या तृणमूल में भी वैसी फूट डालने की तैयारी चल रही है जैसी साल 2022 में महाराष्ट्र की शिवसेना में पड़ी थी?

बागी होने को तैयार 50 विधायक

बंगाल की सियासत में चुनाव के बाद से ही हलचल बनी हुई है। अब दोनों विधायकों को



निकाले जाने के बाद फूट की संभावना को और भी बल मिल रहा है। अटकलें ऐसी भी लगाई जा रही हैं कि करीब 50 विधायक तृणमूल पार्टी से अलग हो सकते हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि कुछ सांसद भी हैं जो बागी तेवर दिखाने की फिराक में हैं और इस बारे में उनकी बातचीत चल रही है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई बैठक से बड़ी संख्या में विधायकों ने दूरी बनाए रखी तो कुछ

विधायक खुलकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है।

ममता का आरोप- बीजेपी डरा रही

ममता बनर्जी ने पार्टी के अंदर मचे घमासान को लेकर अपनी ही पार्टी में मौजूद एक गुट के साथ-साथ बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी डरा-धमकाकर और पैसों का लालच देकर तृणमूल के विधायकों और सांसदों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है और उनकी पार्टी के कुछ नेता गद्दारों जैसा बर्ताव कर रहे हैं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ममता ने एक फेसबुक पर अपने लाइव वीडियो में दावा करते हुए कहा, "चार विधायक मेरे पास शिकायतें लेकर आए थे कि पुलिस उन्हें डरा-धमका रही थी। उनसे यह भी कहा गया कि अगर वे बैठक में शामिल हुए, तो उन्हें 'आर्म्स एक्ट' के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह किस तरह का लोकतंत्र है? इस राज्य में जुल्म की सारी हदें पार हो चुकी हैं।" इससे पहले पिछले हफ्ते शनिवार को कालीघाट में हुई बैठक से तृणमूल के कुल 80 विधायकों में से कम से कम 60 विधायक अनुपस्थित रहे। अंग्रेजी वेबसाइट NDTV ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ठीक उसी समय, कुछ विधायक रथिन घोष के घर पर एकत्र हुए थे। रथिन भी उन विधायकों में शामिल हैं जो ममता की बैठक में शामिल नहीं हुए। उनका कहना है, "मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो सका।"

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बनी बड़ी सहमति



पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति, जल्द हो सकता है ऐतिहासिक समझौता नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते (Trade Deal) के पहले चरण के अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अब समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 4 जून तक नई दिल्ली में वार्ता करेगा। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग के अपर सचिव दर्पण जैन और अमेरिका की ओर से ब्रेंडन लिंच बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों देशों ने 3 फरवरी को समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनाई थी और 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब कानूनी और तकनीकी पहलुओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से भारत के निर्यात, निवेश और रोजगार के अवसरों को नई गति मिल सकती है।

कुशीनगर का फाजिलनगर अब पावागढ़ कहलाएगा: मुख्यमंत्री योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने कुशीनगर दौरे के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फाजिलनगर का नाम बदलकर अब "पावागढ़" किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस घोषणा को भगवान महावीर से जुड़ी ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत से जोड़ते हुए क्षेत्र को नई पहचान देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने 424 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि फाजिलनगर का प्राचीन इतिहास "पावागढ़" और "पावा नगरी" के रूप में जाना जाता रहा है। जैन परंपराओं में इसे भगवान महावीर के महापरिनिर्वाण स्थल से भी जोड़ा जाता है।

विरासत बनाम वोट बैंक की राजनीति

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रही है। उन्होंने



कहा कि जिन स्थानों की पहचान इतिहास में दब गई थी, उन्हें फिर से सम्मान दिलाया जा रहा है।

पर्यटन और धार्मिक महत्व बढ़ाने की तैयारी

सरकार का मानना है कि नाम परिवर्तन से क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। जैन धर्मावलंबियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी इससे बल मिलेगा

और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

राजनीतिक संदेश भी साफ

फाजिलनगर का नाम बदलने का निर्णय केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण और पहचान की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। विपक्ष जहां ऐसे फैसलों पर सवाल उठाता रहा है, वहीं समर्थक इसे ऐतिहासिक न्याय बता रहे हैं।

बड़ा सवाल

क्या नाम बदलने से क्षेत्र का विकास और तेज होगा, या यह केवल प्रतीकात्मक राजनीति का हिस्सा है? इस पर बहस जारी है, लेकिन इतना तय है कि फाजिलनगर से पावागढ़ बनने की यह घोषणा उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक फैसलों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ गई है।

अमेरिका-इजराइल में ईरान लेकर बढ़ रहे मतभेद

मध्य पूर्व की राजनीति में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह दावा कि उन्होंने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बेरूत पर बड़े हमले से रोक दिया, केवल एक सैन्य फैसले की कहानी नहीं है। कई विश्लेषक इसे ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते मतभेदों के संकेत के



रूप में देख रहे हैं।

ट्रंप की प्राथमिकता

व्हाइट हाउस की मौजूदा रणनीति का केंद्र ईरान के साथ किसी प्रकार का समझौता और क्षेत्रीय तनाव को सीमित रखना है। अमेरिका की चिंता यह है कि इजराइल का लेबनान या ईरान समर्थित समूहों पर बड़ा हमला ईरान-अमेरिका वार्ता को पूरी तरह पट्टी से उतार सकता है। तेल आपूर्ति और वैश्विक बाजारों को झटका दे सकता है।